

जमाने में 15 से 20 लाख तक लोगों को रोजगार मिलता था, जबकि आज एक लाख लोगों को भी नहीं मिलता। एक करोड़ रोजगार देने की बात हो रही थी, लेकिन दिया नहीं है। इसकी वजह से ही यह बात है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि इसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे यह सबसे गंभीर बात लग रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए।

सर, इसके साथ-साथ मुस्लिम समाज की स्थिति सबसे बुरी है, यह सबको मालूम है, अभी जावेद भाई ने इसका जिक्र भी किया। मैं कहूंगा कि मुस्लिम समाज को कम से कम शिक्षा में ही रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके बारे में मुम्बई हाई कोर्ट ने भी कहा है। गढ़िया समाज के लिए रिजर्वेशन के बारे में समाज को सोचना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: हम मराठा आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री हुसैन दलवाई: सर, सरकार को ये तीन चीजें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि वह इनके बारे में जल्दी हल निकाले।

श्रीमती वंदना चव्हाण (महाराष्ट्र): महोदय मैं स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

श्री सभापति: प्रो. मनोज कुमार झा।

Demand of the Several Social Groups for reservation

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, देश के अलग-अलग हिस्सों में आरक्षण को लेकर आवाजें उठ रही हैं। अभी हुसैन दलवाई साहब ने मराठा आंदोलन का जिक्र किया, मेरा मानना है कि अलग-अलग हलकों में, अलग-अलग सामाजिक समूहों में आरक्षण को लेकर एक आवाज उठ रही है। मैं सदन के माध्यम से तमाम जिम्मेवार सत्ता और विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि आरक्षण के लिए संविधान सभा की बैठकों में यह तय हुआ था कि यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह प्रतिनिधित्व का मामला है, लेकिन 1991 के बाद हमने जो विकास की एक नव-उदारवादी पूंजीवाद की शक्ति अख्तियार कर ली, उसकी वजह से समानता के महासागर में पांच समृद्धि के टापू बने। जाति और गरीबी पिछड़ेपन का सीधा रिश्ता है, लेकिन कई अन्य जातियाँ, जो आरक्षण की मांग कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि संजीदगी से सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आंकड़े, सत्ता प्रतिष्ठान से हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूँ कि उसको जारी कीजिए। जातियों को पता चले कि उनकी आबादी कितनी है, उनकी अवस्थिति कितनी है। सर, उसके अभाव में अलग-अलग हलकों में जो यह आवाज उठ रही है, यह ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इसको संजीदगी से एप्रोच करने की जरूरत है, अन्यथा यह ज्वालामुखी सब लील जाएगा, हमारी उपलब्धियों को भी लील जाएगा।

श्री सभापति: ठीक है, थैंक यू। श्री के.सी. राममूर्ति।

Need to include the World Heritage site Hampi in the 'Must See List' of the ASI

SHRI K. C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, all of us know that Hampi, the capital of Vijayanagara Empire in Karnataka is recognised globally for its temple complexes

[Shri K. C. Ramamurthy]

and has also received the UNESCO World Heritage recognition. UNESCO has described Hampi as 'austere and grandiose', but it amuses me, Sir, that the released 'Must See List' of ASI has left out Hampi which is a disgrace to the nation in general and Karnataka in particular. Sir, the 'Must See List' contains monuments and other very important sites in the country which are exceptional in terms of art and architecture, planning and design, engineering marvels and a testimony to the civilizational past, but, I am sure no one in this House would disagree with me when I say that Hampi in Karnataka qualifies beyond these prescriptions. I am shocked how come ASI has left out Hampi when UNESCO itself has recognised it as a world heritage site. Sir, the hon. Minister is on record saying that Hampi was left out by overlooking it. It is not just overlooking, Sir. It is being neglected, if I may say so, and it has been removed from the list. How can a site like Hampi, which has thousands of years of legacy be overlooked? In view of the above, I demand through you, Sir, the Government of India to immediately include Hampi in the 'Must See List' of ASI without any further delay.

SHRI D. KUPENDRA REDDY (Karnataka): Sir, I associate myself with Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. K. V. P. RAMACHANDRA RAO (Telangana): Sir, I also associate myself with Zero Hour Mention made by the hon. Member.

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I too associate myself with Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I associate myself with Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I associate myself with Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्री हुसैन दलवाई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

Need to declare the Eastern Rajasthan Canal Project as National Project

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान): माननीय सभापति जी, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ देश के कुल भूभाग का 10.41 परसेंट भूभाग है और वहाँ पर मात्र एक प्रतिशत बरसात होती है। इन सब स्थितियों को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है और वह यह है कि चम्बल और उसकी सहायक नदियों का जो पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है, उसको व्यवस्थित